



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1938 (श0)
(सं0 पटना 37) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जनवरी 2017

सं० 08/आरोप-01-314/2014-15771 सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

25 नवम्बर 2016

श्री राजेन्द्र राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-502/11, तत्कालीन निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया के विरुद्ध हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन में अनियमितता बरतने से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1431, दिनांक 28.10.2014 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क' सहित) पर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-209386, दिनांक 21.11.2014 द्वारा श्री राम के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। विभागीय पत्रांक-16999, दिनांक 10.12.2014 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। मामले की गम्भीरता के मद्देनजर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित करते हुए श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-3197, दिनांक 26.02.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री राम के अनुरोध पर प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ के स्थान पर विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया (विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13011, दिनांक 01.09.2015)

2. विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-43 (अनु०) दिनांक 29.01.2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसकी प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-2126, दिनांक 10.02.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर श्री राम से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री राम ने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 29.02.2016) समर्पित किया।

3. आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरान्त निम्न स्थिति पाया गया :-

- (क) अररिया जिला के चार विधान सभा क्षेत्रों यथा अररिया, जोकिहाट, रानीगंज एवं फारबिसगंज में विधायक मद से कुल 36 हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कार्यकारी एजेन्सी के चयन एवं भुगतान में हुई अनियमितता के इस मामले में कुल राशि रुपये 1,58,11,200.00 (एक करोड़ अन्दावन लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) के राजस्व की क्षति निहित है।

(ख) वस्तुतः कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध 80 प्रतिशत राशि विमुक्त किये जाने के बावजूद कार्यकारी एजेन्सी द्वारा एक भी हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापित एवं क्रियाशील नहीं किये जाने के कारण उनके विरुद्ध प्राथमिकी (485/2009, दिनांक 19.10.2009) भी दर्ज हुई।

(ग) उक्त योजना में हुई अनियमितता का संज्ञान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा भी लेखा परीक्षा (सिविल) वर्ष-2009-10 की प्रस्तावित कंडिका 2.4.1 के रूप में लिया गया।

(घ) उक्त योजना में गबन की गयी राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से करने हेतु निलाम पत्र वाद दायर हुआ।

4. वस्तुतः तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया के पद पर पदस्थापन के दौरान (दिनांक 11.01.07 से दिनांक 15.12.2008) हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कार्यकारी एजेन्सी के चयन में श्री राम द्वारा बिहार वित्त नियमावली की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण चयनित एजेन्सी का स्थायी पता प्राप्त नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद संवेदक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी तथा निलाम पत्र वाद दायर होने के बावजूद उनसे राशि की वसूली नहीं हो सकी। एजेन्सी ने एक भी हाई मास्ट लाईट क्रियाशील नहीं किया इसके बवजूद 80 प्रतिशत योजना राशि का भुगतान किया गया।

5. श्री राम ने अपने लिखित अभिकथन में वित्तीय नियमों को अनदेखी करते हुए कार्यकारी एजेन्सी को अग्रिम प्रदान करने में निहित प्रमाणित आरोपों पर कोई ठोस तर्क प्रस्तुत किये बिना केवल कार्यदेश निर्गत करने के औचित्य को सही बताया है। निर्धारित अधिसीमा से ज्यादा अग्रिम देने के साथ-साथ एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन करने पर भी द्वितीय किस्त (अग्रिम) विमुक्त कर दिया गया। इस संबंध में लिखित अभिकथन में कोई युक्ति-युक्त कारण नहीं दर्शाया गया। यद्यपि द्वितीय किस्त की विमुक्ति का आधार सहायक विधुत अभियंता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को बताया गया है तथापि एक भी हाई मास्ट लाईट पूर्ण रूप से अधिष्ठापित नहीं होने की भौतिक स्थिति के आलोक में उक्त अग्रिम विमुक्ति करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। हाई मास्ट लाईट के विधुत विपत्र भुगतान एवं उसके रख-रखाव हेतु जिम्मेवारी का निर्धारण किये बिना ही योजना का कार्यान्वयन कराया गया। इन आरोपों के संबंध में लिखित अभिकथन में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. वर्णित स्थिति में राजस्व क्षति में निहित आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक-12385, दिनांक 09.09.2016 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2141, दिनांक 19.10.2016 से प्राप्त हुई।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री राजेन्द्र राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-502/11 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 में प्रावधानित शास्ति निम्नवत संसूचित की जाती है :-

(क) 03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 37-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>